न्यायमूर्ति विकास बहल के समक्ष

जी. हेमवती– याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य– उत्तरवादी

सी.आर.आर. नंबर 764 - 2021

26 अगस्त, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 439 (2) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ एक्ट, 1985 – धारा 21 (सी) – सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश करते समय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन के लंबित होने के तथ्य का खुलासा न करना जमानत रद्द करने का आधार नहीं है।

यह *निर्धारित किया गया* कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोहन सिंह (उपर्युक्त) के मामले में विशेष रूप से कहा था कि केवल इस तथ्य के कारण कि एक अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है, सत्र न्यायालय को यह बताए बिना कि उसने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था, यह उस जमानत को रद्द करने का आधार नहीं होगा जो पहले ही दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता का मामला उक्त निर्णय द्वारा पूर्ण रूप से लागू होता है। यहां तक कि उक्त निर्णय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत आवेदन (अनुबंध पी -1) के विस्तृत उत्तर (अनुबंध पी 2) के पैरा 7 में संदर्भित किया गया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश में उक्त निर्णय पर विचार नहीं किया गया है।

(पैरा 10)

आदित्य सांघी,
याचिकाकर्ता के वकील।
प्रवीण भादू, एएजी, हरियाणा। (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

विकास बहल, जे.

(1) यह 16.07.2021 के आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका है, जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा ने याचिकाकर्ता को दी गई नियमित जमानत को रद्द करने की कृपा की, जिसे आईपीसी की धारा 21 (सी) के तहत 21.03.2021 को एफआईआर नंबर 37 में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत दायर एक आवेदन में 28.06.2021 के आदेश के तहत दिया गया था।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, पुलिस स्टेशन डिंग, जिला सिरसा, हरियाणा में मुख्य रूप से इस आधार पर दर्ज किया गया था कि सत्र न्यायालय के

समक्ष नियमित जमानत आवेदन के साथ हलफनामे में याचिकाकर्ता की बेटी ने नियमित जमानत के लिए याचिका के बारे में उल्लेख नहीं किया था जो इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और लंबित थी।

(2) याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में, सिरसा के सत्र न्यायाधीश ने 28.06.2021 (अनुबंध पी -3) के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को जमानत दे दी थी, जो 63 वर्षीय महिला है। उक्त आदेश का संदर्भ दिया गया है जिसमें सिरसा के सत्र न्यायाधीश ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की गई थी और सह-आरोपी हरमिंदर सिंह और नत्था सिंह के प्रकटीकरण बयान के अलावा वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अभियोगात्मक सबूत नहीं था, जिनसे कथित वसूली की गई थी। आगे यह देखा गया कि याचिकाकर्ता 22.03.2021 से हिरासत में था।

(3) याचिकाकर्ता के वकील ने **सीआरएम-एम-12051-2020** में इस न्यायालय की एक सह-नियुक्त पीठ द्वारा 17.06.2021 को पारित फैसले पर भरोसा किया है, जिसका शीर्षक **"मेवा सिंह बनाम पंजाब राज्य"** है और **सीआरएम-एम-12997-2020** में पारित निर्णय जिसका शीर्षक **"दलजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य"** है, यह तर्क देने के लिए कि केवल सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर याचिकाकर्ता को जमानत की रियायत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। **मेवा सिंह** के प्रासंगिक हिस्सा के फैसले को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

> "1. याचिकाकर्ता ने इस अदालत से अनुरोध किया है कि उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 133 दिनांक 24.11.2019 के तहत धारा 21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम पुलिस स्टेशन लोहियां, जिला जालंधर के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत दी जाए।
>
> 2. प्रतिवादी-राज्य की ओर से श्री प्यारा सिंह, पीपीएस, पुलिस उपाधीक्षक, उप-मंडल शाहकोट, जिला जालंधर (ग्रामीण) के हलफनामे का जवाब दाखिल किया गया है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।
>
> 3. आरोप है कि बचित्तर सिंह के पास से 1.7 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पूछताछ के दौरान, उन्होंने याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित करते हुए एक खुलासा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति की गई थी।
>
> 4. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसे मौके पर कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और कथित प्रकटीकरण बयान विश्वसनीयता के लायक नहीं है।

5. याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए उसकी संलिप्तता पूर्ण रूप से स्पष्ट है क्योंकि वह तीन अन्य मामलों में शामिल है यानी एफआईआर नंबर 43 दिनांक 2.4.2016 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, पुलिस स्टेशन सुल्तानपुर लोधी; एफआईआर नंबर 5 दिनांक 5.1.2020 के तहत धारा 307, 186, 332, 353, 224, 225, 427, 148, 149 आईपीसी, थाना सुल्तानपुर लोधी और एफआईआर नंबर 193 दिनांक 193 दिनांक 22.11.2019 को धारा 15, 21, 25, 29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ एक्ट, पुलिस स्टेशन करतारपुर।

6. मैंने इस न्यायालय के समक्ष संबोधित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

7. यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता को मौके पर कभी नहीं पकड़ा गया था और उसके खिलाफ एकमात्र सबूत प्रकटीकरण बयान के रूप में है, जिसकी स्वीकार्यता और सत्यता का परीक्षण दयालु के दौरान किया जाएगा। अन्य तीन मामलों के संबंध में जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित हैं, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि उक्त मामलों में भी उन्हें झूठा फंसाया गया है और उन्हें मौके पर कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और उन्हें तीनों मामलों में अग्रिम जमानत दी गई है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह एक ऐसा मामला है जहां याचिकाकर्ता को केवल प्रकटीकरण विवरण के आधार पर नामित किया गया है, याचिका स्वीकार की जाती है और यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी / जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए उसके व्यक्तिगत बांड और जमानत बांड जमा करने के उपरांत जमानत पर रिहा किया जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता को जब भी ऐसा करने के लिए बुलाया जाएगा, वह जांच में शामिल होगा और गिरफ्तार/जांच अधिकारी के साथ सहयोग करेगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (2) के तहत प्रदान की गई शर्तों का भी पालन करेगा।

9. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता जांच में शामिल नहीं होता है, तो जांच एजेंसी/अभियोजन पक्ष उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ सकता है।"

(4) दलजीत सिंह (उपरोयुक्त) के फैसले का प्रासंगिक हिस्सा नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"याचिकाकर्ता ने धारा के तहत अग्रिम जमानत देने की मांग की स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 15, 18, 27ए, 29 के तहत धारा 140, 188, 216, 419, 420, 467, 468, 471, 474 आईपीसी और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 के तहत पुलिस स्टेशन पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र में

एफआईआर संख्या 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयान के आधार पर फंसाया गया है, जिनके पास से 248 किलोग्राम चूरा पोस्त, 1 किलो 500 ग्राम अफीम और 199 किलोग्राम खस खस बरामद किया गया था।

गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता का नाम पुलिस के रूका में नहीं आया।

याचिकाकर्ता के पक्ष में जांच में शामिल होने के लिए अंतरिम निर्देशों के साथ 27.05.2020 को नोटिस जारी किया गया था।

दिनांक 27.05.2020 के आदेश को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया जा रहा है।

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 15,18,27-क,29 के तहत अपराधों के लिए दिनांक 8.4.2020 की एफआईआर संख्या 188 में याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत तत्काल याचिका दायर की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसे केवल सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयान के आधार पर मामले में झूठा फंसाया गया है, जिनके पास से 248 किलोग्राम चूरापोस्त, 1 किलोग्राम 500 ग्राम अफीम और 199 किलोग्राम खस खस बरामद किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि उसके झूठे आरोप का तथ्य इस तथ्य से और मजबूत होता है कि उपरोक्त मादक पदार्थ की बरामदगी गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी और उसका नाम न तो पुलिस द्वारा भेजी गई रूका में था और न ही एफआईआर में इस तथ्य के साथ कि उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। वह इसी तरह के किसी अन्य मामले में भी शामिल नहीं है।

10.07.2020 के लिए प्रस्ताव की सूचना।

न्यायालय के कहने पर, श्री सौरभ मोहनता, डीएजी, हरियाणा ने नोटिस स्वीकार कर लिया।

इस बीच, याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और जांच एजेंसी / जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। उसकी उपस्थिति पर, उसे गिरफ्तार/जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को जब भी बुलाया जाएगा, जांच में शामिल होना चाहिए और दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 438 (2) के तहत निर्दिष्ट शर्तों का पालन करना होगा। **27.05.2020**

इसके बाद, राज्य की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था।

राज्य का रुख यह है कि याचिकाकर्ता उस कैंटर की सुरक्षा कर रहा था जिसमें प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद था और उसे रास्ते में पुलिस की उपस्थिति के मामले में इशरा करने देने का कर्तव्य सौंपा गया था।

राज्य के वकील याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के कॉल विवरण, टॉवर लोकेशन पर भरोसा करते हैं और सह-आरोपी के खाते में राशि जमा करने वाले बैंक स्टेटमेंट पर भी भरोसा करते हैं। जिस सामग्री पर विद्वान राज्य वकील भरोसा करता है, वह प्रासंगिक स्तर पर उस संदर्भ में नेतृत्व किए जाने वाले सबूतों पर निर्भर करता है।

याचिकाकर्ता जांच में शामिल हो गया है, लेकिन राज्य के वकील ने उपरोक्त आधार पर याचिकाकर्ता की हिरासत की मांग की है।

पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, मैंने पाया कि सह-आरोपी बलबीर और राजिंदर के प्रकटीकरण बयान के आधार पर शामिल याचिकाकर्ता **तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य**, **आपराधिक अपील संख्या 2013 की 152,** के अनुपात से प्रभावित है, जिसमें यह देखा गया है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 53 के तहत जिन अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं, वे सादय अधिनियम की धारा 25 के अर्थ के भीतर पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत माना जाएगा। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 67 के तहत बयान को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कुछ भी अर्थ लगाए बिना दिनांक 27.05.2020 के आदेश की पुष्टि करना उचित होगा।

तदनुसार आदेश दिया।

हालांकि, याचिकाकर्ता जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक होने पर जांच में शामिल होना जारी रखेगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 (2) के तहत परिकल्पित शर्तों का पालन करेगा।

याचिका का निपटारा किया जाता है।"

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे बताया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया गया था, लेकिन स्टेशन हाउस ऑफिसर ने दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, मुख्य रूप से इस आधार पर कि याचिकाकर्ता की बेटी के हलफनामे में, जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत आवेदन के साथ था, यह कहा गया है कि "वर्तमान जमानत याचिका धारा के तहत दूसरी जमानत याचिका है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 और पहला आवेदन इस माननीय न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था", हालांकि, **सी.आर.एम-एम-19144-2021** के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था, जो याचिकाकर्ता के लिए नियमित जमानत की मांग करते हुए इस न्यायालय में दायर किया गया था और लंबित था। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आवेदन का एक विस्तृत जवाब दायर किया गया था जिसमें कई कानूनी बिंदु उठाए गए थे। सबसे पहले यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया गया था और वह अदालत की हिरासत में थी और इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने का सवाल ही नहीं उठता है। उक्त प्रावधान का भी संदर्भ दिया गया है, जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"439. जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां।

(1) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है-

XXX---XXX---XXX

(2) उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय निर्देश दे सकता है कि इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में लिया जाए।"

(6) यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि यह केवल उस मामले में लागू होगा जहां इस अध्याय के तहत जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है और हिरासत में रखा जाना है। चूंकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कभी जमानत पर रिहा नहीं किया गया था और वह अदालत की हिरासत में था, इस प्रकार, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने और उसे हिरासत में लेने का सवाल ही नहीं उठता था। उक्त आवेदन के पैरा 7 का भी उल्लेख किया गया जिसमें 1978 की आपराधिक अपील संख्या 118 में सर्वोच्च न्यायालय के 20.2.1978 के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसका शीर्षक **मोहन सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़** है, जिसमें यह देखा गया था कि केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जमानत आवेदन के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। इसमें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग नहीं की जाएगी। उक्त निर्णय के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"अपीलकर्ता के खिलाफ इस मामले में कथित अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत है। सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत दी गई थी, लेकिन दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद इसे उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से इस कारण

से रद्द कर दिया गया था कि अपीलकर्ता ने सत्र न्यायालय को बताए बिना सत्र के साथ-साथ उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इससे स्वाभाविक रूप से उच्च न्यायालय को लगा कि पार्टी अदालत के साथ उनके व्यवहार में स्पष्ट नहीं थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले से दी गई जमानत को खारिज कर दिया।

राज्य के वकील ने हमारे सामने दबाव डाला कि जिस भ्रष्टाचार के लिए अपीलकर्ता प्रथम दृष्टया दोषी था (जांच के परिणामों के अनुसार) वह पर्याप्त था। आइए हम ऐसा मानते हैं। फिर भी जमानत से इनकार करना किसी आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। यह जमानत के औचित्य के बारे में एक भ्रम है। इस अदालत ने गुरचरण सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में जमानत कानून के वास्तविक आधार की व्याख्या की है। (1) हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता के खिलाफ अभी तक न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप या जमानत से इनकार करने के लिए अन्य स्थापित आधारों पर कोई आरोप है। इस विचार में, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को सत्र न्यायालय द्वारा पारित अगले आदेश तक जमानत पर जारी रखने की अनुमति दी जाए, यदि इसकी संतुष्टि के लिए अच्छे आधार बनाए जाते हैं।

अपील की अनुमति दी गई।"

(7) यह भी प्रस्तुत किया गया था कि त्रुटि, यदि कोई थी, तो वह प्रमाणित थी और जानबूझकर नहीं थी और याचिकाकर्ता या उसकी बेटी के खिलाफ कोई आरोप नहीं था कि वे जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे या याचिकाकर्ता द्वारा गवाहों पर दबाव डालने की कोई संभावना थी। आवेदन में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इस आशय का भी अनुरोध किया गया था कि जमानत रद्द करने का काम बहुत सख्त है और इसका सहारा केवल असाधारण मामलों में ही लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि यह याचिकाकर्ता नहीं था जिसने कोई गलत बयानी की थी क्योंकि वह खुद हिरासत में थी। याचिकाकर्ता की बेटी ने भी गलत बयान नहीं दिया था, लेकिन अनजाने में हुई गलती के कारण, केवल पहली जमानत याचिका के बारे में उल्लेख किया था और उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक विविध याचिका के बारे में उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि वह कानूनी विशेषज्ञ नहीं होने के नाते कानून की पेचीदगियों के बारे में नहीं जानती थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा कोई कॉलम नहीं था जिसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका का भी खुलासा करने की आवश्यकता थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जवाब में रुख के अनुसार, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता मानसिक आघात से गुजर रहा था, क्योंकि याचिकाकर्ता जो कि पीड़ित की मां है और जो कभी भी किसी भी मामले में शामिल नहीं थी, उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा ने मामले के उक्त पहलुओं और कानूनी स्थिति पर विचार

किए बिना, दिनांक 28.06.2021 के आदेश के तहत दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, यहां तक कि प्रतिवादी राज्य द्वारा दायर विस्तृत हलफनामे के अनुसार, यह स्पष्ट है कि चालान पहले ही 16.06.2021 को दायर किया जा चुका है और मामले में जांच पूरी हो गई है। सिरसा के पुलिस उपाधीक्षक श्री संजय कुमार के हलफनामे के पैरा 6 का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें पैराग्राफ 6 में कहा गया है कि याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता 63 वर्ष की एक वृद्ध महिला है, उसे बुढ़ापे की कई समस्याएं हैं और वह 22.03.2021 से हिरासत में है और अपनी बेटी द्वारा अनजाने में की गई गलती के लिए पर्याप्त पीड़ित है। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा है कि वास्तव में यह याचिकाकर्ता अपने वकील के माध्यम से था, जिसने सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के तथ्य को इस न्यायालय के ध्यान में लाया था। वर्तमान याचिका में 30.07.2021 को प्रस्ताव की सूचना जारी किए जाने पर समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश का और संदर्भ दिया गया है। उक्त आदेश निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।

याचिकाकर्ता के वकील ने 1978 की आपराधिक अपील संख्या 118 में 'मोहन सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़' शीर्षक वाले फैसले को सेवा में रखा है, जिसे शीर्ष अदालत ने 20.02.1978 को उनके तर्क के समर्थन में तय किया था कि याचिकाकर्ता को दी गई नियमित जमानत की रियायत को सिरसा के सत्र न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से वापस ले लिया गया है, क्योंकि उसने नियमित जमानत के लिए याचिका के तथ्य को छिपाया था। वह इस न्यायालय के समक्ष लंबित है, जब इसी तरह की राहत देने के लिए तरस रही याचिका विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। वकील ने आगे तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अभी तक हिरासत से बाहर नहीं आई है, क्योंकि उसने आवश्यक बांड जमा नहीं किए थे।

प्रस्ताव की सूचना।

श्री गौरव बंसल, एएजी, हरियाणा, प्रतिवादी-राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। स्थगित तिथि पर, राज्य के वकील याचिका पर विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे।

16.08.2021 की सूची।"

(8) सरी ओर, राज्य के वकील ने राज्य द्वारा दायर किए गए जवाब का हवाला दिया है और प्रस्तुत किया है कि हालांकि याचिकाकर्ता से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन 23.03.2021 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद, उससे 1,06,000 रुपये की राशि बरामद की गई है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी को हलफनामे में आपराधिक विविध याचिका के बारे में भी उल्लेख करना चाहिए था जो इस न्यायालय में

लंबित थी, जिसमें नियमित जमानत देने के लिए प्रार्थना की गई थी क्योंकि वह वही थी जो मामले की देखभाल कर रही थी। आगे कहा गया है कि अब मामले को 02.09.2021 के लिए आरोप तय करने के लिए निर्धारित किया गया है।

(9) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और उसकी राय है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए और आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।

(10) मोहन सिंह (उपेरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से कहा था कि केवल इस तथ्य के कारण कि एक अभियुक्त ने सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की है, सत्र न्यायालय को यह बताए बिना कि उसने उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, यह उस जमानत को रद्द करने का आधार नहीं होगा जो पहले ही दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता का मामला उक्त निर्णय द्वारा पूर्ण रूप से कवर किया गया है। यहां तक कि उक्त निर्णय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत आवेदन (अनुबंध पी -1) के विस्तृत उत्तर (अनुबंध पी -2) के पैरा 7 में संदर्भित किया गया था। हालांकि, आक्षेपित आदेश में उक्त निर्णय पर विचार नहीं किया गया है।

(11) इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि जब 28.06.2021 के आदेश के तहत दी गई जमानत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत जमानत रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया गया था , तो याचिकाकर्ता जो 63 वर्ष की एक वृद्ध महिला है, अदालत की हिरासत में थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 (2) के तहत प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि रद्द करने की मांग ऐसी स्थिति में की जा सकती है जहां व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और उसे गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की मांग की गई है। इस प्रकार, जिस आवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है, वह कानूनी रूप से सुनवाई योग्य नहीं था। इसके अलावा, उक्त आवेदन पर दायर विस्तृत जवाब के पैराग्राफ 3 में इसके संबंध में विशिष्ट आपत्ति ली गई थी, हालांकि, विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरसा ने आक्षेपित आदेश में उक्त महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है। इस प्रकार, केवल उक्त दो पहलुओं पर, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान याचिकाकर्ता, जो 63 वर्ष की एक वृद्ध महिला है, यहां तक कि राज्य द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता 22.03.2021 से हिरासत में है, चालान पहले ही दायर किया जा चुका है और अब मामले में 02.09.2021 को आरोप तय करने की तारीख तय की गई है और इस प्रकार, मुकदमे में समय लगने की संभावना है। याचिकाकर्ता को अपनी बेटी द्वारा की गई गलती के लिए दो महीने तक और कैद का सामना करना पड़ा है और उसे हर समय हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब विद्वान सत्र न्यायाधीश

ने अपने 28.06.2021 के अपने पिछले आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को जमानत का हकदार पाया था।

(12) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी जाती है और दिनांक 16.07.2021 के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है।

(13) यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 28.06.2021 का पिछला आदेश, इस प्रकार, लागू होगा।

(14) चूंकि मुख्य पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय ले लिया गया है, इसलिए लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

सुमति जुंड

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

रोहतास,
(अनुवादक)